

मुख्य समाचार

- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा—एफ.आर.ए. प्रावधानों के तहत सड़कों के नियमितीकरण के लिए समीक्षा याचिका दायर करेगा वन विभाग।
- राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल को नशे से बचाने के लिए राजनीतिक दलों से आगे आने का किया आह्वान।
- केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा— हिमाचल में केंद्र की करोड़ों रुपये की निर्माणाधीन परियोजनाओं में प्रदेश सरकार नहीं दे रही सहयोग।
- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर धुवीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप।

एफसीए— मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि वन विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करके निर्मित सड़कों के नियमितीकरण की मांग को लेकर 10 मई, 2025 से पहले न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की जाएगी। शिमला में आज वन विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने जनहित को ध्यान में रखते हुए ऐसी सड़कों के नियमितीकरण के लिए कानूनी सहायता लेने की आवश्यकता पर बल दिया और इस संबंध में विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में ऐसी 2 हजार एक सौ 83 सड़कें हैं, जिनमें शिमला जोन में 6 सौ 13, मंडी में 8 सौ 21, हमीरपुर में 2 सौ 54 और कांगड़ा जोन में 4 सौ 95 सड़कें शामिल हैं। ये सड़कें राज्य में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निर्मित की गई है जिसे हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2016 में लागू किया गया था। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

भेंट

प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की और पिछले दो वर्षों में उनके मानदेय में दो गुना वृद्धि करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान को प्राथमिकता दे रही है और इस संबंध में अनेक कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्रों में नशे की समस्या को रोकने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों में सक्रिय सहयोग देने का आह्वान भी किया।

राज्यपाल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजनीतिक दलों से हिमाचल को नशे से बचाने के लिए आगे आने का आह्वान किया है। उन्होंने आज कांगड़ा जिला के इंदौरा में नशा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत आयोजित नशा विरोधी जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि जब तक हम नशे को खत्म नहीं करेंगे, तब तक प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नशामुक्त भारत की सोच से ही संभव हुआ है और अब यह जन आंदोलन बन चुका है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के समय छात्रों को शपथ पत्र देना होगा जिसमें वे नशा न करने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में नशा विरोधी कानून पारित करने की सलाहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में उन्होंने स्वयं इस अभियान की अगुवाई की है और प्रदेशभर में इस सामाजिक बुराई के खिलाफ जागरूकता फैलाने का जिम्मा उठाया है। इस दौरान सांसद राजीव भारद्वाज और विधायक मलेन्द्र राजन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

कांग्रेस बैठक

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी नेताओं से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा-निर्देश पर प्रदेश में संविधान बचाव अभियान में बढ़चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया है। शिमला में आज पार्टी नेताओं की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल को शिमला के चौड़ा मैदान में संविधान बचाव रैली का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा देशभर में झूठ फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में प्रदेश के हितों की अनदेखी हुई और बल्क ड्रग पार्क में भी प्रदेश की संपदा को लूटने की कोशिश की गई।

अजय टम्टा

केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार की 73 हजार करोड़ रुपये की फोरलेन, एन.एच.ए.आई. और सेतुबंदन सहित विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं। वे आज शिमला में आंबेडकर सम्मान सभा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अजय टम्टा ने कहा कि इन परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण में प्रदेश की सुक्खू सरकार सहयोग नहीं कर रही है जिसके चलते विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का हमेशा अपमान किया और कभी उन्हें चुनाव नहीं जीतने दिया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के सम्मान के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा और केंद्र की मोदी सरकार आज उन्हें सम्मान दे रही है। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस का काम केवल गांधी परिवार को बचाना रह गया है।

जयराम

इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज मंडी में आयोजित बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर सम्मान अभियान के तहत आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भीमराव आंबेडकर ने दलितों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए जीवनभर संघर्ष किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा उनका अपमान किया और सत्ता हासिल करने के लिए संविधान का दुरुपयोग किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज मोदी सरकार बाबा साहेब के सम्मान के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस मौके पर प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री सिद्धार्थन और सांसद सुरेश कश्यप सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बीच जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कांग्रेस नेता देशभर में नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार का बचाव कर रहे हैं, जो बहुत शर्मनाक व दुर्भाग्यपूर्ण है।

अशोक गहलोत

वरिष्ठ कांग्रेस नेता व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर धुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सरकार केंद्रीय एजेंसियों ईडी, सीबीआई का प्रयोग कर झूठे मामले बना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश की विरासत को बचाने का काम किया है और गांधी परिवार का देश की आजादी में अहम योगदान रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और भाजपा विपक्षी पार्टियों को दुश्मन की तरह देख रही है जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।